STATUTORY RESOLUTION

Approving Proclamation issued by President on January 19, 2009, in relation to State of Jharkhand

and

MOTION

Recommending to the President Revocation of Proclamation issued on January 19, 2009, in relation to State of Jharkhand

GOVERNMENT BILLS — *contd.*

The Jharkhand Appropriation (Vote on account) Bill, 2009

and

The Jharkhand Appropriation Bill, 2009

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (DR. SHAKEEL AHMAD): Sir, I move:

That this House approves the Proclamation issued by the President on the 19th January, 2009, under article 356(1) of the Constitution in relation to the State of Jharkhand.

SHRI YASHWANT SINHA (Jharkhand): Sir, I move:

That this House recommends to the President that the Proclamation issued by her on January 19, 2009 under article 356 of the Constitution in relation to the State of Jharkhand be revoked.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI PAWAN KUMAR BANSAL): Sir, I beg to move:

That the Bill to provide for the withdrawal of certain sums from and out of the Consolidated Fund of the State of Jharkhand for the services of a part of the financial year 2009-10, as passed by Lok Sabha, be taken into consideration.

Sir, I also beg to move:

That the Bill to authorise payment and appropriation of certain further sums from and out of the Consolidated Fund of the State of Jharkhand for the services of the financial year 2008-09, as passed by Lok Sabha, be taken into consideration.

The questions were proposed.

SHRI YASHWANT SINHA (Jharkhand): Mr. Deputy Chairman, Sir, what has happened over the last two days with regard to the discussion on his issue is, in a way, symptomatic of the state in which the State of Jharkhand is. This discussion was scheduled to come yesterday which could not for paucity of time. Then, it was listed to come up immediately after the

Question Hour today. But, again, fate intervened and we bow to the convenience of the hon. Minister of External Affairs and Finance and the discussion is coming up now. I have changed my programme a number of times in order to be able to participate in this discussion. सर, मैं अपनी बात की शुरुआत इस बात से करता हूँ कि झारखंड का और इंडो-यूएस न्यूक्लियर डील का क्या सम्बन्ध है? शायद एक सम्बन्ध बहुत स्पष्ट है कि जो यूरेनियम माइंस झारखंड के जादूगोड़ा में हैं, उस बारे में अभी सीएजी की एक रिपोर्ट आई कि वहां जितना प्रोडक्शन होना चाहिए था, उतना प्रोडक्शन नहीं किया गया और इंडो-यूएस न्यूक्लियर डील करनी पड़ी, लेकिन एक दूसरा संबंध भी है, क्योंकि इंडो-यूएस न्यूक्लियर डील को पास कराने के लिए दूसरे सदन में सरकार ने एक विश्वास-मत लाया और विश्वास-मत में बहुमत हासिल करने के लिए इस डील के लिए बहुत सारी डील हुईं, जिसमें एक झारखंड की भी डील थी और उस डील के अंतर्गत यह डील हुई कि झारखंड में जो सरकार चल रही थी, वह सरकार बदली गई। वहां मुख्यमंत्री मधु कोडा हट गए और श्री शिबू सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री बन गए। इस तरह देखा जाए, तो उस डील के तहत यह डील हुई और उसके बाद शिबू सोरेन जी को एक षडयंत्र के तहत एक ऐसे क्षेत्र से विधान सभा का चुनाव लड़ने के लिए प्रेरित किया गया, जहां उनका कोई बेस ही नहीं था। झारखंड मुक्ति मोर्चा का तमार में कोई बेस नहीं था, इसलिए उनका हारना वहां से अवश्यंभावी था और वही हुआ कि श्रीमान शिबू सोरेन जी चुनाव हार गए और झारखंड में राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ा। आज इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हम यहां पर खड़े हैं। अगर इंडो-यूएस न्यूक्लियर डील नहीं हुई होती, तो मधु कोडा नहीं हटे होते, शिबू सोरेन मुख्यमंत्री नहीं बने होते, तमार का उप-चुनाव वह नहीं लड़े होते, फिर मुख्यमंत्री पद से वह नहीं हटे होते और वहां राष्ट्रपति शासन नहीं लगा होता। तो आप देखिए, इंडो-यूएस न्यूक्लियर डील का कितना असर झारखंड के ऊपर पड़ा? यह इससे स्पष्ट है। ...(**व्यवधान**)... कभी-कभी ऐसा होता है कि म्युजिकल इंस्ट्रूमेंट में आप यहां पर उंगुली लगाते हैं कि एक तरह की आवाज होगी, लेकिन कहीं और से दूसरी तरह की आवाज निकल आती है। इसमें ठीक वैसा ही हुआ।

महोदय, इसमें मैंने एक मोशन मूव किया और आपने उसकी अनुमति दी। मैंने कहा कि राष्ट्रपति महोदय को यह प्रोक्लेमेशन वापिस लेना चाहिए। मेरा एतराज क्या है? मेरा एतराज यह है कि झारखंड में राष्ट्रपति शासन मात्र 6 महीने के लिए क्यों लगाया जाय? झारखंड में तो राष्ट्रपति शासन, अगर संविधान में संशोधन करने की आवश्यकता हो, तो वह संशोधन करके, बराबर के लिए लगा देना चाहिए। ...(**व्यवधान**)... हां, हमेशा के लिए। मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूँ कि झारखंड में एक महीना भी नहीं हुआ, राष्ट्रपति शासन लगने के 22-24 दिन में ऐसा चमत्कार हुआ है, जो आज तक भारत के इतिहास में नहीं हुआ। मैंने ऐसा कोई रिजीम नहीं देखा है, ऐसा कोई शासन नहीं देखा है, उपसभापति महोदय, जिसमें कि एक महीना पूरा होने के बाद वह शासन अपनी उपलब्धियों को लाखों-करोड़ों रुपया खर्च करके न केवल झारखंड की जनता के सामने, बल्कि देश की जनता के सामने ले आए। हमारे जो राज्यपाल महोदय हैं, झारखंड में, मैं समझता हूँ कि शायद हम सब लोग यहां बैठकर प्रणब बाबू की तारीफ कर रहे थे, बहुत अच्छे हैं, हम सब उस तारीफ में शामिल थे, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि झारखंड को एक ऐसा निराला राज्यपाल मिला है, जिसने ऐसा चमत्कार कर दिया कि उस चमत्कार को, उन उपलब्धियों को दुनिया को बताने के लिए दो-दो पेज का एडवर्टाइजमेंट दिल्ली के अखबारों में निकला। यह एक महीने की उपलब्धि है। प्रणब बाबू यहाँ बैठे हुए हैं, मैं इनसे यह सिफारिश करूंगा कि ऐसे विरले व्यक्ति को आप झारखंड में कहाँ waste कर रहे हैं? झारखंड के लिए वह बहुत ऊंचे हैं। आप उनको यहाँ लाइये। अगर प्रधान मंत्री की vacancy हो तो उस कुर्सी पर उनको बिठा दीजिए। अगर आप कोई मंत्रालय छोड़ना चाहते हैं तो वह मंत्रालय उनको दीजिए। जिस आदमी ने झारखंड में इतना बड़ा चमत्कार सिर्फ 30 दिनों में कर दिया तो आप सोचिये कि वह देश में कितना बड़ा चमत्कार कर सकता है! इसलिए अगर देश के पैमाने में उनकी उपलब्धियों का उपयोग करें तो यह देश को बहुत काम आएगा।

7.00 P.M.

राज्यपाल का पद एक संवैधानिक पद है। इस बात को हम सब मानते हैं कि नहीं कि यह संविधान का पद है? क्या हम व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए संविधान के पद का दुरुपयोग कर सकते हैं? मैं इस सदन, जो कि Council of States है, के सामने इस बात को रखना चाहता हूँ। यहाँ पर यह बात उठनी चाहिए, मैं बहुत गंभीरता के साथ इसको उठा रहा हूँ। इस प्रकार का दो पेज़ में advertisement देना — यह दिल्ली का अखबार है, दो full पेज। मैंने पता किया कि एक full पेज advertisement देने में कितना खर्च आता है तो पता चला कि 25 लाख रुपये आता है। इस प्रकार, दो full पेज के 50 लाख रुपये हुए। झारखंड के अखबारों में दो-दो पेज का छपा है। इतना बड़ा फोटो छापकर क्या दिखाने की कोशिश हो रही है?

एक माननीय सदस्य: सर, यह किसका फोटो है?

श्री यशवंत सिन्हा: यह फोटो है * का जो वहाँ के राज्यपाल हैं। यहाँ देखिये, इतना बड़ा फोटो छपा है।

श्री उपसभापति: आप नाम मत लीजिए।

श्री यशवंत सिन्हा: क्यों नहीं? हम लेंगे। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर यह * का पर्सनल बखान नहीं होता तो मैं राज्यपाल की बात करता।

श्री उपसभापति: नाम निकाल दीजिए।

श्री यशवंत सिन्हा: लेकिन इसका क्या मतलब है?

श्री उपसभापति: सबको मालूम है।

श्री यशवंत सिन्हा: सबको क्या मालूम है? हम नाम लेकर इसीलिए कह रहे हैं — उपसभापति महोदय, मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि क्या यह संवैधानिक दृष्टिकोण से सही कदम है कि 22 दिन पूरे होने के बाद, एक महीना पूरा होने के बाद झारखंड सरकार के लाखों-करोड़ों रुपये खर्च करके इस प्रकार उपलब्धियों का एक विज्ञापन दिया जाए? इतना बड़ा फोटो, पर्सनल प्रमोशन और आप कहते हैं कि मैं नाम नहीं ले सकता हूँ! ...(**व्यवधान**)...

श्री एस.एस. अहलुवालिया: क्या राष्ट्रपति कर सकते हैं ...(**व्यवधान**)...

श्री यशवंत सिन्हा: क्या राष्ट्रपति कर सकते हैं, हमारे मित्र पूछ रहे हैं। सर, यह वही राज्यपाल महोदय हैं, मैं इस सदन को याद दिलाना चाहूँगा, जिन्होंने जब 2005 में झारखंड विधानसभा के चुनाव हुए, एन0डी0ए0 majority MLAs को लेकर राज्यपाल के सामने चारों तरफ प्रदर्शन कर रही थी, फिर भी उन्होंने जिनके पास majority नहीं थी, यानि कि श्री शिबू सोरेन, उनको उन्होंने मुख्यमंत्री की शपथ दिला दी। उन्होंने उनको शपथ ही नहीं दिलाई बल्कि उनको तीन हफ्ते का समय भी दिया कि तीन हफ्ते के बाद आप विधान सभा में अपना बहुमत सिद्ध करो। तीन हफ्ता! हम लोग majority लेकर घूम रहे हैं, MLAs को लेकर घूम रहे हैं, राष्ट्रपति के यहाँ गये कि देखो, हमारे पास majority है, क्या हो रहा है झारखंड में? Ultimately, हम सुप्रीम कोर्ट में गये और सुप्रीम कोर्ट ने दो दिन के भीतर 9 मार्च, 2005 को कहा कि यह सरकार जो आपने बनाई है, यह अपनी majority proof करे। Naturally, उस सरकार के पास majority थी ही नहीं तो वह proof कहाँ से करती? तब श्री शिबू सोरेन जी ने क्या किया? उन्होंने इस्तीफा दिया, इस्तीफा देना ही एक विकल्प था और तब जाकर वहाँ एन0डी0ए0 की सरकार बनी। वहाँ एन0डी0ए0 की सरकार बन गई और यह सरकार अच्छी चल रही थी — लेकिन यह बहुत सारे मित्रों को भा नहीं नहीं रहा था, सुहा नहीं रहा था। इसलिए लोग लगे रहे। झारखंड का शुरू से ही दुर्भाग्य रहा कि जब सन् 2000 में झारखंड राज्य का निर्माण हुआ, तब से वहाँ की सरकारें, चाहे किसी की भी सरकार हो, वह कुछ निर्दलीय विधायकों पर निर्भर रहीं। दुर्भाग्य से वर्ष 2005 में भी जो संतुलन था, बैलेंस था, वह निर्दलीय विधायकों के पास ही रहा। अगस्त, 2006 आते-आते, हमारे जो मित्र उधर बैठे हैं, इनको यह सफलता मिल गई कि इन्होंने कुछ निर्दलीय विधायकों को अपनी तरफ कर लिया। कैसे किया ...(**व्यवधान**)...

---

*Not recorded.

सुश्री मैबल रिबैलो: यह सही नहीं है, हम लोगों ने नहीं किया ...(**व्यवधान**)...

श्री यशवंत सिन्हा: ठीक है, वे खुद चलकर आपके पास आ गए ...(**व्यवधान**)...

सुश्री मैबल रिबैलो: उन्होंने इनको छोड़ दिया ...(**व्यवधान**)...

श्री यशवंत सिन्हा: उपसभापति जी, मैं मेबल जी से कभी लड़ाई कर ही नहीं सकता हूं, इसलिए मैं इस बात को स्वीकार करता हूं ...(**व्यवधान**)...

श्री एस.एस. अहलुवालिया: उनको नींद में चलने की आदत थी ...(**व्यवधान**)...

श्री यशवंत सिन्हा: उनको नींद में चलने की आदत थी, इसलिए वे नींद में चलते हुए हमारी तरफ से इनकी तरफ चले गए ...(**व्यवधान**)... इन्होंने कुछ नहीं किया, ये चुपचाप बैठे हुए थे कि तुम्हारी सरकार चल रही है, चलने दो, तब तक वे लोग स्वतः हमसे टूटकर इनकी तरफ चले गए, जाकर इनके दरवाजे पर दस्तक दी, बहुत जोर से दस्तक दी, इन्होंने पूछा कि कौन है, पता चला कि निर्दलीय विधायक हैं, इन्होंने कहा कि ठीक है, आ जाओ। वे निर्दलीय विधायक हमारा साथ छोड़कर स्वतः इनकी तरफ चले गए और उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद विश्व के प्रजातांत्रिक इतिहास में झारखंड ने एक अनूठा स्थान बनाया। वहां पर हमारे बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा सबसे बड़ा दल था, उसके 17 विधायक थे, कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, इन सब दलों ने कहा कि हम जिम्मेदारी नहीं संभालेंगे। JMM जिम्मेदारी नहीं संभालेगा, कांग्रेस पार्टी जिम्मेदारी नहीं संभालेगी, RJD जिम्मेदारी नहीं संभालेगी। अब मुख्य मंत्री कौन बनेगा? एक निर्दलीय मुख्य मंत्री बनेगा। अब जो निर्दलीय विधायक थे, श्री मधु कोड़ा, जिनको हमने 2005 में टिकट नहीं दिया, तो वे स्वतंत्र रूप से चुनाव में खड़े हुए, जनता ने उनका साथ दिया और वे किस्मत के भी धनी थे, अतः जीत गए। जब हमारे यहां से कोई जाता है, तो वह अचानक सेक्युलर बन जाता है, इसलिए वे सेक्युलर बन गए थे। वे सेक्युलर ही नहीं बन गए, वे भारी सेक्युलर हो गए, वे इतने बड़े सेक्युलर हो गए कि उसके बाद इन लोगों ने उचित समझा कि उन्हीं को मुख्य मंत्री बनाया जाए और विश्व के इतिहास में यह अनूठा अनुभव हमारे सामने आया कि बड़े-बड़े दलों की बड़ी-बड़ी संख्या होने के बावजूद एक निर्दलीय को झारखंड का मुख्य मंत्री बना दिया गया और बाकी सारे निर्दलीय, मंत्री बन गए। JMM ने सोचा कि बहती गंगा में हम भी डुबकी लगा लें, इसलिए वे भी सरकार में शामिल हो गए, लेकिन कांग्रेस पार्टी और RJD, इन दोनों ने यह कहा कि हम बाहर से समर्थन करेंगे। यह सरकार करीब 2 साल तक चली, जब तक कि Indo US Nuclear Deal का हस्तक्षेप नहीं हुआ और तब जाकर मधु कोड़ा का पटाक्षेप हो गया। वह बेचारा निर्दलीय अकेला क्या करता? वे निर्दलीय ही नहीं थे, निर्दयी भी थे, वे निर्दलीय, मधु कोड़ा को भी छोड़कर चले गए और शिबू सोरेन के साथ हो लिए। तब शिबू सोरेन जी की सरकार बन गई और उसके बाद जैसा मैंने आपसे कहा कि उनको तमार से चुनाव लड़ा दिया गया। अब झारखंड में बहुत कहानियां चलती हैं कि कांग्रेस पार्टी ने कहा कि नहीं, तमार से ही लड़ लो, हम लोग पूरा समर्थन करेंगे ...(**व्यवधान**)... शिबू सोरेन का तमार से दूर-दूर तक कोई लेना-देना नहीं है, वे बेचारे तमार से खड़े कर दिए गए। अब यह भारत के इतिहास में शायद दूसरा या तीसरा उदाहरण होगा कि एक serving मुख्य मंत्री चुनाव हार गया। वह चुनाव हार गए। नतीजे कब आए? 8 जनवरी को नतीजे आए। 8 तारीख को तीन बजे तक यह क्लीयर हो गया कि शिबू सोरेन हार गए हैं और भारी मतों से हार गए हैं। उस समय मैं रांची में था और मैं यह सोच रहा था कि अभी यह खबर आएगी कि वह इस्तीफा देंगे, लेकिन 8 तारीख गुजर गई, उनका कोई इस्तीफा नहीं आया। 9 तारीख गुजर गई, उनका इस्तीफा नहीं आया। 10 तारीख गुजर गई, उनका इस्तीफा नहीं आया। फिर 11 तारीख भी गुजर गई, लेकिन उनका इस्तीफा नहीं आया।

सुश्री मैबल रिबैलो: महोदय, उसने 11 तारीख को इस्तीफा दे दिया है।

श्री यशवंत सिन्हा: नहीं, उसने 12 तारीख को इस्तीफा दिया है। उसके बाद वह दिल्ली का चक्कर लगा रहे हैं, हर दरबार में जा रहे हैं कि मेरे को दोबारा चुनाव लड़ने की अनुमति दो। मधु कोड़ा के जैसा ही हमारे

एक विधायक थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया कि यहीं से शिबू सोरेन चुनाव लड़े। लेकिन खैर मैं यूपीए सरकार या यू0पी0ए0 गठबंधन को साधुवाद देता हूँ कि इन्होंने कहा कि नहीं, नहीं, अब बहुत हो गया, तुम चुनाव हार गए हो, अब तुम छोड़ कर जाओ। जब इन्होंने न कर दिया, तब उन्होंने 12 तारीख को इस्तीफा दिया। इस्तीफा दिया तो फिर राज्यपाल महोदय क्या कहते? उन्होंने कहा कि काम चलाऊ सरकार, काम चलाऊ मुख्य मंत्री की तरह काम करो। उसके बाद 19 जनवरी को वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू हुआ। जैसा मैंने आपसे कहा कि अभी एक महीना यानी तीस दिन भी पूरा नहीं हुआ था कि राज्यपाल महोदय ने अपना बखान करते हुए ये सब विज्ञापन निकाले कि साहब, झारखंड में क्या-क्या चमत्कार हो गया, क्या-क्या परिवर्तन हो गया। मैं तो वहां बहुत आता-जाता हूँ, लेकिन मुझे कहीं कोई एक पत्ता भी हिलता हुआ नजर नहीं आया। साहब, इतना जबर्दस्त परिवर्तन और इतना बड़ा परिवर्तन कहां हुआ? उसके बाद हम लोगों ने कहा, हम इस बात को जानते हैं कि जब तक राष्ट्रपति शासन को दोनों सदनों की मंजूरी नहीं मिलेगी, तब तक सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार विधान सभा भंग नहीं हो सकती है। उपसभापति महोदय, सुप्रीम कोर्ट के फैसले में यह नहीं कहा गया है कि राज्यपाल महोदय विधान सभा को भंग करने की सिफारिश भी नहीं करे। भले ही भारत सरकार उसे भंग करने का फैसला नहीं करे, लेकिन राज्यपाल महोदय विधान सभा भंग करने की सिफारिश कर सकते हैं।

उपसभापति महोदय, 12 जनवरी को शिबू सोरेन जी ने इस्तीफा दे दिया और आज हम लोग 25 फरवरी को बात कर रहे हैं। इतने दिन बीत गए, लेकिन अभी तक कोई सिफारिश नहीं है। एक जिसे घोड़ा मंडी कहते हैं, वहां वही घोड़ा मंडी खुली हुई है और अभी भी खरीद-फरोख्त की कोशिश जारी है कि कोई एक सरकार बन जाए। मैं यह कहना चाहता हूँ कि यह जो opening है, यह क्यों खुली छोड़ी? यह दरवाजा खुला छोड़ने का क्या मतलब है? राज्यपाल महोदय ने यह सिफारिश क्यों नहीं की कि वहां पर कोई लोकप्रिय सरकार नहीं बन सकती है, कोई प्रजातांत्रिक सरकार नहीं बन सकती है, इसलिए झारखंड विधान सभा को भंग किया जाए। आज मैं यहां पर मंत्री महोदय से आग्रह करना चाहूंगा कि जब वे यहां जवाब देने के लिए उठें, तो कृपया यहां पर बिल्कुल स्पष्ट करें कि यहां की मंजूरी मिलने के बाद भारत सरकार झारखंड विधान सभा को भंग करेगी। वहां पर नया जनादेश लिया जाएगा, वहां की जनता को अवसर दिया जाएगा कि वह एक नई सरकार चुने और जो चुन जाए, वह फिर वहां पर सरकार बनाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसी क्रम में हम लोग राज्यपाल महोदय के पास हाथ जोड़कर निवेदन करने गए कि कम-से-कम सिफारिश तो कर दीजिए। तब तक उन्होंने हमारे ऊपर जो कहर ढहाया, वह मैं इस सदन के सामने बयां कर चुका हूँ।

उपसभापति महोदय, झारखंड का क्या हुआ? भारत के इर्द-गिर्द बहुत सारे देश हैं, हम उनके बारे में कहते हैं कि "India is surrounded by 'failed States'." यहां पर विदेश मंत्री जी बैठे हैं, पाकिस्तान में कुछ development हुआ है। बांग्ला देश में तो बहुत भयंकर development हुआ है। पाकिस्तान में नवाज शरीफ और उनके भाई को अयोग्य घोषित कर दिया गया है। अब वे चुनाव लड़ ही नहीं सकते हैं। और जब हम आ रहे थे तो आप ही के एक वरिष्ठ मंत्री से हम लॉबी में बात कर रहे थे — वैसे यहां लॉबी की बात का जिक्र करना उचित नहीं है लेकिन फिर भी उसमें कोई ऐसी बात नहीं है, इसलिए मैं बता रहा हूं — उन्होंने कहा कि हम लोग यहां पर कितनी ऊंची परम्पराओं को maintain करके चल रहे हैं। मैंने कहा कि यह बात बिल्कुल सही है। भारत में अगर प्रजातंत्र बचा हुआ है तो यह हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि है। चारों तरफ failed states हैं। लेकिन जब हम देश के भीतर झांकते हैं तो हम पाते हैं कि झारखंड आज की तारीख में नम्बर वन failed State है। आठ साल पहले जब NDA की सरकार ने झारखंड का निर्माण किया था, तब हमने दूर-दूर तक कल्पना भी नहीं की थी कि झारखंड का यह हश्र होगा। महोदय, इस सदन में उस प्रदेश का प्रतिनिधि होने के नाते, उस प्रदेश का एक नागरिक होने के नाते आज मैं बहुत वेदना के साथ आपसे कह रहा हूं कि झारखंड corruption का, maladministration का एक पर्याय बन चुका है। एक ऐसी स्टेट जो भारत को रास्ता दिखा सकती थी, उसके बारे में आज यह हो रहा है कि अगर मैं कहीं पर जाता हूं और कोई मुझसे पूछता है कि आप किस राज्य से राज्य सभा के सदस्य हैं। मैं जब बताता हूं कि मैं झारखंड का हूं तो हमारे बगल में जो लोग बैठे होते हैं,

वे थोड़ा खिसक जाते हैं कि यह झारखंड का है, पता नहीं इसके पास कोई कट्टा, बंदूक या dagger क्या हो। इस तरह की स्थिति है। आज 24 में से 20 जिले वहां नक्सलवाद से प्रभावित हैं। यह स्थिति आज वहां पर है। मैं आपसे बहुत अदब के साथ कहना चाहता हूं कि हम लोग, जो झारखंड में राजनीति करते हैं, वहां पर अपनी जान को हथेली पर रखकर राजनीति करते हैं। हम लोग जब अपने क्षेत्र में जाते हैं तो हमें यह नहीं पता होता है कि रात को हम सही सलामत घर लौटेंगे या नहीं लौटेंगे। कहां lineman मिलेगा, कहां पर आक्रमण हो जाएगा, यह कहना मुश्किल है। हमारा जिला तथा हमारे इर्द-गिर्द जितने जिले हैं, वे भयंकर ढंग से नक्सलवाद से प्रभावित हैं। जिस राज्य को भगवान ने सब कुछ दिया, जादूगुडा की यूरेनियम माइन्स जहां दीं, वह झारखंड इतनी गुरबत में होगा, इतना भाग्यहीन होगा, यह कल्पना के परे बात है। लेकिन यही आजकल वहां पर हो रहा है। अभी कुछ दिन पहले हमारे गृह मंत्री महोदय झारखंड गए थे। सारे जिला पदाधिकारियों और पुलिस कप्तानों को उन्होंने बुलाया और उनके साथ बैठक की। उस बैठक के बाद राज्यपाल महोदय ने एक और बैठक की। उसमें भी उन्होंने जिला पदाधिकारियों को बुलाया। मैं मंत्री महोदय से कहूंगा कि वे इस बात की पड़ताल कर लें, उनके जो पदाधिकारी official gallery में बैठे हैं, उनसे वे पूछ लें, क्योंकि वहां के अखबारों में यह खबर छपी थी कि देश के गृह मंत्री को भी गुमराह किया गया, उनको गलत आंकड़े दिए गए। जब राज्यपाल महोदय ने मीटिंग की तो वहां दूसरे आंकड़े दिए गए और जब गृह मंत्री ने मीटिंग की तो कुछ और आंकड़े दिए गए। महोदय, हज़ारीबाग के बगल का एक जिला चतरा है। चतरा घोर नक्सलवाद से प्रभावित क्षेत्र है। चतरा के बारे में जब सवाल पूछा गया तो कोई बताने को तैयार नहीं था। तब एक महिला पदाधिकारी, आई.ए.एस. पदाधिकारी आगे आयीं और उन्होंने गृह मंत्री से कहा कि सर, मैं वहां दस महीने के लिए डिप्टी कमिश्नर थी। तब गृह मंत्री जी ने पूछा कि दस महीने ही क्यों? तब पता चला कि दस महीने के बाद उनका तबादला हो गया। लेकिन उस पूजा सिंहल का, जो चतरा में दस महीने डिप्टी कमिश्नर रही, इस सदन को सुनकर घोर आश्चर्य होगा, दो महीने में उनका ट्रांसफर...।

श्री उपसभापति : सिन्हा जी, मंत्री जी को जाना है, वे एक स्टेटमेंट करना चाहते हैं।

INFORMATION TO THE HOUSE

Developments in Bangladesh

THE MINISTER OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI PRANAB MUKHERJEE): Sir, I have to leave as I have some assignment. A delegation is coming to see me. In the morning I had informed in response to Mr. Ahluwalia*ji* that I would ascertain from our High Commissioner in Bangladesh as to what has happened. What is happening there is absolutely their internal matter and naturally we would not like to make any comment on it. But this much I can share that in Bangladesh there is an elected Government. People have reposed their faith and confidence in the elected Government. It is their matter; they will handle it. Our best wishes are always with Bangladesh. So far as our border is concerned, it is absolutely secured. Our BSF and other security forces are protecting our border. It is exclusively their internal matter and they are tackling it. I do hope it will be resolved and the local Government is competent enough to take care of them. They have their sovereign Government and they will deal with it in the best possible manner as they feel necessary. This much information I would like to share as Mr. Ahluwalia*ji* requested me, and I will request that we should not discuss or seek any clarification on it. Thank you.